THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : (a) Feature films have been imported in the recent past from Australia, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Czechoslovakia, Ethiopia, France, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Mali, Morocco, Newzealand. Poland, Senegal, Swedan, Trinidad, Tunisia, Turkey, Upper Volta, United Kingdom, United States of America, USSR, West Germany, Yugoslavia etc.

(b) Import of feature films is made by the National Film Development Corporation except to the extent provided for in the Policy for import of films formulated by the Ministry of Information and Broadcasting. According to the exceptions provided for in the Policy, private Indian importers can import films out of those entered in the Market Section of the International Film Festival/Filmotsav organised in India and approved by the National Film Development Corporation within the amount sanctioned by the Government and by the Sovexportfilm from USSR, subject to a monetary limit laid down by the Government. Till 30th September, 1983, Motion Picture Export Association of American were also permitted to import films in accordance with the agreement entered into by them with the Government, subject to the limitations laid down in the agreement. Generally, NFDC imports films on outright purchase basis or on profit-sharing basis, Private importers can import films only on outright purchase basis. In the case of Sovexportfilm/MPEAA Companies, their Indian branches import/imported prints of films from their principals for distribution in India. Private importers, Sovexportfilm and MPEAA Companies pay/paid canalising fee to National Films Development Corporation, the official canalising agency.

(c) and (d) The information in being collected.

विद्युत का उत्पादन और उसकी सस्ती दरों पर पूर्ति

1324. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है और इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों का ब्योरा क्या है;

(ख) पनबिजली और ताप विद्युत का अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में और किस अनुपात में उत्पादन होता है;

(ग) ताप और पनबिजली के उत्पादन की प्रति यूनिट लागत क्या है और इन लागतों में क्या अन्तर है; और

(घ) सस्ती दरों पर बिजली की पूर्ति किए जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ महोम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान देश में ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों में उत्पादित विद्युत और उनका अनुपात अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन का स्वरूप	उत्पादन मेगावाट आवर	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1981-82	ताप विद्युत	70346	57.2
	जल विद्युत	49558	40.3
	न्युक्लीय	3021	2.5
	जोड :	122925	
1982-83	ताप विद्युत	81261	61.8
	जल विद्युत	48273	36.7
	न्युक्लीय	2024	1.5
	जोड :	131558	
1983-84	ताप विद्युत	86535	61.9
	जल विद्युत	49867	35.6
	न्युक्लीय	3494	2.5
	जोड :	139896	

(ग) और (घ) विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की लागत एक परियोजना में दूसरी परियोजना पर अलग-अलग होती है जो परियोजना की लागतें परियोजना के आकार, स्थल, की परिस्थितियों, प्रचालित मूल्यों के स्तर और ब्याज की दरों, ईंधन और अन्य निवेशों की लागत तथा प्रचालन सम्बन्धी पैरामीटरों आदि पर निर्भर करती है । हाल ही में अनुमोदित की गई जलविद्युत परियोजनाओं से होनी वाली विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत 25 से 65 पैसे प्रति यूनिट भिन्न-भिन्न है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में मूल्यांकित की गई ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन की लागत 36 पैसे से 75 पैसे प्रति यूनिट तक भिन्न-भिन्न है। जल विद्युत ताप विद्युत का उत्पादन के उपयुक्त मिश्रण की आयोजना की जाती है परन्तु उत्पादन की लागतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत सस्ती दरों पर दे पाना व्यवहार्य होगा ।

Vacancies of Judges in Supreme Court

1325. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the number of vacancies of Judges existing in the Supreme Court at present and the likely position by the end of 1984 ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : At present, no vacancy of a Judge exists in the Supreme Court. No vacancy will arise by way of retirement during 1984.